आत्मनिर्भर और खुशहाल भारत के निर्माण की ओर अग्रसर

BRLF

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

सरकार से साझेदारी में स्वयं सेवी संस्थाओं के कार्य के विस्तार हेतु भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्था।

विषयसूची

पृष्ठ 01

भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउंडेशन की पृष्ठभूमि

पृष्ठ 03

माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध

पृष्ठ 05

बीआरएलएफ का उद्देश्य

पृष्ठ 07

बीआरएलएफ के प्रमुख कार्यक्षेत्र

पृष्ठ 08

बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार

पृष्ठ 09

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं

पृष्ठ 12

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य के साथ तालमेल

पृष्ठ 13

राज्य सरकार की साझेदारी के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

पृष्ठ 15

विमुक्त/घुमंतू पारधी समाज के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए पायलट परियोजना

पृष्ठ 16

क्षमता-वर्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यक्रम

पृष्ठ 18

अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन

पृष्ठ 18

जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्कृष्टता केंद्र

पृष्ठ 19

रीमा कच्छप: सफलता की उड़ान

भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउंडेशन की पृष्ठभूमि

भारत की आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत मध्य भारत के दस राज्यों में निवास करता है। इस क्षेत्र में भारत के अधिकांश गरीब आदिवासी निवास करते हैं जिन्हें भारत की विकास प्रक्रिया का अधिकतम लाभांश नहीं मिल पाया है और ऐतिहासिक उपेक्षा की वजह से सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा के हर संकेतक पर उनका विकास सूचकांक निम्न रहा है।

बढ़ती असमानता को लेकर भारत सरकार ने **'समावेशी विकास'** की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और ख़ासकर जनजाति कल्याण के लिये कई योजनाओं को सुचारू रूप चलाया गया है। भारी वित्तीय परिव्यय से समर्थित योजनाओं द्वारा, सरकार बड़ी संख्या में संसाधनों का निवेश इन क्षेत्रों में कर रही है। हालांकि, अभी भी विभिन्न कारणों से इन योजनाओं का पूरा लाभ आदिवासी समाज को नहीं मिल पा रहा है। यह तभी साकार किया जा सकता है, जब आदिवासी समुदाय, संगठित होकर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों, आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं के लिए वे अपेक्षित क्षमताओं को विकसित करें और हर स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में विकास और शासन को मज़बूत एवं प्रबल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त और पारदर्शिता के साथ कार्य करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था की परिकल्पना करते हुए भारत रूरल लाईवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) को प्रस्तावित किया था। बीआरएलएफ भारत के सबसे अविकसित और आदिवासी क्षेत्रों में समग्र विकास और सुशासन लाने के उद्देश्य से स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। जिसकी स्थापना वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा की गई थी।

बीआरएलएफ की आम सभा और कार्यकारी समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, शिक्षा जगत, नागरिक समाज, उद्योग जगत, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। बीआरएलएफ, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा ऑडिट के अधीन है, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सोसायटी पर लागू होता है।

वर्ष 2012-13 के बजट भाषण में, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित घोषणा कीः
"आजीविका के माध्यम से भारत लाईवलीहुड्स फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव है। फाउंडेशन लगभग 170 जिलों के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं का समर्थन और विस्तार करेगा। निजी ट्रस्टों और परोपकारी संगठनों को स्वायत्त निकाय के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिसे पेशेवर रूप से प्रबंधित किया जाएगा।" (बजट भाषण का पैरा 111)

माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध

बीआरएलएफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प के प्रति कटिबद्ध होकर अपने सभी परियोजनाओं में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश को समर्पित योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, गैर कीटनाशक प्रबंधन (एनपीएम) आधारित कृषि, और सहभागी भूजल प्रबंधन को सम्मिलित किया है। बीआरएलएफ की परियोजनाओं को सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों के कामकाज में सुधार एवं असरदार बनाने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर बीआरएलएफ द्वारा समर्थित किया गया है।

बीआरएलएफ द्वारा चयनित CSO को वित्त पोषित किया जाता है ताकि वे अपने तकनीकी ज्ञान एवं अनुभव से सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में अपना योगदान दे सके। CSO द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वयन करने वाली संस्था जैसे पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता वर्धन किया जाता है जिससे वे बेहतर तरीक़े से कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करने में सक्षम हो सके। इस प्रकार बीआरएलएफ की परियोजनाएं यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका हैं कि सरकार के प्रमुख कार्यक्रम सुचारू रूप से और प्रभावी ढंग से चल रहे हैं, और यह कि वे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम हैं।

उल्लेखनीय आँकड़े

275,154
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (जॉब कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन) से लाभान्वित परिवार

206,207
प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े परिवार

143,076
प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े परिवार

107,993
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

64,011
ग्रामीण पेयजल योजना/स्वच्छता के माध्यम से समर्थित परिवार

62,341
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

62,031
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

50,599
प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

21,997
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

9,923
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

7,749
प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

4,779
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जुड़े परिवार

135,052 अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित परिवार

बीआरएलएफ का उद्देश्य

बीआरएलएफ एक ऐसे ग्रामीण भारत की कल्पना करता है जहां प्रत्येक समुदाय विशेषतः आदिवासी और महिलाएँ सशक्त हैं और उनके पास सतत् एवं स्थायी आजीविका है। वे सक्रिय रूप से समुदाय आधारित संगठनों जैसे ग्राम पंचायत, ग्राम सभा,
स्वयं सहायता समूह तथा विभिन्न प्रकार के उत्पादक संगठनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। महिलाएं इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका के रूप में उभर कर आएँ।

बीआरएलएफ का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी में सामाजिक एवं आर्थिक योजनाओं और गतिविधियों को प्रोत्साहित कर मध्य भारत के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों और विशेष रूप से महिलाओं को सतत् एवं स्वचालित आजीविका और जीवनयापन के अवसरों को प्रदान करना है। बीआरएलएफ स्थानीय जनजातीय समुदायों को उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। बीआरएलएफ स्थानीय समुदायों को संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करके और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर पैदा करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए भी काम करता है। बीआरएलएफ आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण कार्यकर्ताओं के कौशल और ज्ञान को विकसित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

प्रमुख उद्देश्य:

- **सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रम के व्यय और अपेक्षित परिणामों के बीच के अंतर को कम करना**
- **आदिवासी लोगों के बीच अलगाव की भावना को समाप्त कर भारतीय लोकतंत्र में उनका विश्वास जीतना**
- **सिविल सोसाइटी संस्थानों (CSOs)को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे प्रमुख सरकारी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता में सुधार ला सकें**
- **राज्य सरकारों, सिविल सोसाइटीज, पंचायती राज संस्थाओं और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी (CSR) के बीच साझेदारी एवं भागीदारी को बढ़ावा देकर मध्य भारतीय जनजाति क्षेत्रों में समावेशी विकास करना**
- **मध्य भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में अग्रणी ग्रामीण पदाधिकारियों की कार्यकारी संस्थाओं का क्षमता निर्माण**
- **कृषि और जल प्रबंधन में समुदाय-आधारित सतत् प्रथाओं को सशक्त कर उन्हें बड़े पैमाने पर विकसित करना**

पिछले दस वर्षों में बीआरएलएफ ने सरकार, सिविल सोसाइटी संस्थाओं (CSOs) एवं अन्य दानदाता संस्थाओं के सहयोग के माध्यम से जमीनी स्तर पर एक सार्थक विकासात्मक परिणाम के कई नये आयाम स्थापित किए हैं। इनमें बीआरएलएफ की भूमिका वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों तरह की रही है। मुख्य रूप से, बीआरएलएफ ने सरकारी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को मुख्यधारा में लाने और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से एक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों के मुताबिक़ सबसे प्रभावी ढंग से सक्षम बनाने में सफलता हासिल की है।

बीआरएलएफ के प्रमुख कार्यक्षेत्र

सिविल सोसाइटी संस्थाओं (CSOs) को अनुदान सहायता प्रदान करना

बीआरएलएफ का प्रमुख कार्यक्षेत्र सिविल सोसाइटी संस्थाओं (CSOs) के उत्कृष्ट कार्यों का केंद्र एवं राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में विस्तार करना है। बीआरएलएफ ने सिविल सोसाइटी संस्थाओं (CSOs) के चयन हेतु एक विस्तृत एवं मज़बूत प्रक्रिया को समाहित किया है। इस प्रक्रिया के तहत अच्छे एवं कार्य निपुण सीएसओ का चयन किया जाता है, और उन्हें अनुदान सहयोग दिया जाता है ताकि वे अपने अनुभवों एवं तकनीकी ज्ञान से प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार एवं योगदान प्रदान कर सकें।

क्षमता निर्माण - जमीनी स्तर पर व्यक्तिगत क्षमता का निर्माण करना

बीआरएलएफ शैक्षणिक संस्थानों, विशेषज्ञों और डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स की मदद से आदिवासी युवा और सामुदायिक संस्थाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है इसके साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, और सिविल सोसाइटी संस्थाओं को सह-शिक्षण प्लेटफार्मों की सुविधा भी मुहैया कराता है।

अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन

बीआरएलएफ का अनुसंधान वर्टिकल मुख्य रूप से कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न शोध एवम् नीति पत्र निकालने का कार्य, प्रमुख कार्यक्रमों पर नीति संक्षिप्त विवरण तथा सर्वोत्तम प्रथाओं और अभिनव परियोजनाओं पर केस अध्ययन आयोजित करने का कार्य करता है।

बीआरएलएफ का भौगोलिक विस्तार

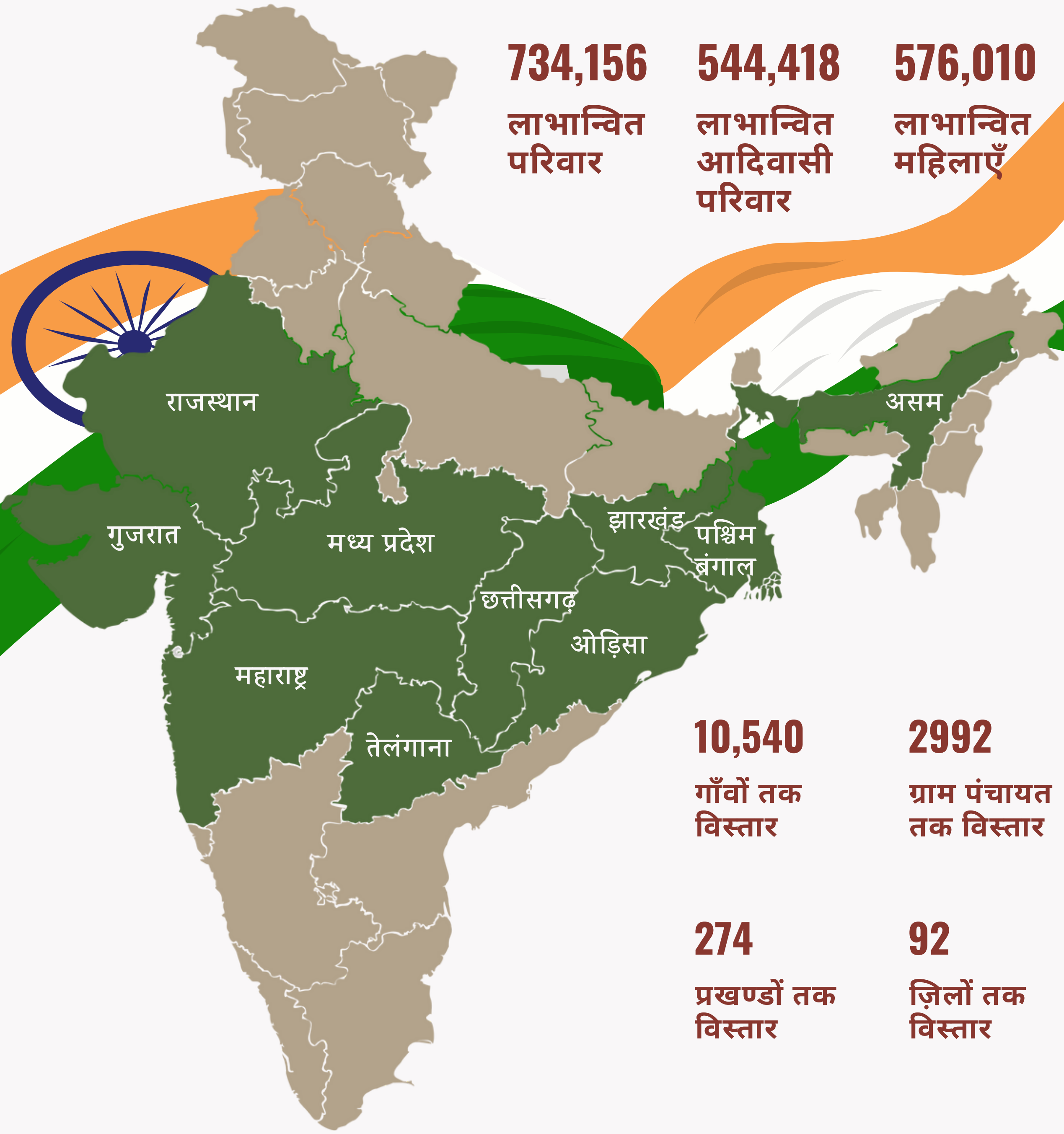

734,156
लाभान्वित परिवार

544,418
लाभान्वित आदिवासी परिवार

576,010
लाभान्वित महिलाएँ

10,540
गाँवों तक विस्तार

2992
ग्राम पंचायत तक विस्तार

274
प्रखण्डों तक विस्तार

92
ज़िलों तक विस्तार

बीआरएलएफ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बोडोलैंड और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के साथ करार (MoU) करके इन राज्यों में हाई इंपैक्ट परियोजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है।

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं

ऊसरमुक्ति मेगा वॉटरशेड परियोजना

पश्चिम बंगाल सरकार

विभाग: राज्य मनरेगा सेल

ऊसरमुक्ति परियोजना के तहत बीआरएलएफ और राज्य मनरेगा सेल के द्वारा स्थाई आजीविका में वृद्धि की दिशा में पश्चिम बंगाल के पश्चिमी भाग में वाटरशेड मोड में मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से 2000 माइक्रो वॉटरशेड का नियोजन और क्रियान्वयन रिज टू वैली सिद्धांत के आधार पर किया गया है। परियोजना के दूसरे चरण में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अन्तर्गत सृजित आधारभूत संरचनाओं पर सतत् आजीविका उत्पादन को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। लघु और सीमांत किसानों के लिए 80,000 रुपये से अधिक की स्थायी वार्षिक घरेलू आय में वृद्धि किया जा रहा है। ऊसरमुक्ति परियोजना के अंतर्गत 218,862 लघु एवं सीमांत परिवार लाभान्वित हुए हैं।

हाई इम्पैक्ट मेगा वॉटरशेड परियोजना

छत्तीसगढ़ सरकार

विभाग: राज्य मनरेगा सेल

परियोजना का मुख्य उद्देश्य वाटरशेड मोड में मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन करना जिसमें मुख्य रूप से मिट्टी और जल संरक्षण पहलों में निवेश के माध्यम से लघु और सीमांत किसानों की आजीविका में सुधार करना है। वाटरशेड प्रबंधन और कृषि उत्पादकता के माध्यम से स्थायी आधार पर किसानों की आय में वृद्धि करना। इस परियोजना के अन्तर्गत 127,927 परिवार लाभान्वित हुए हैं और लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन का ट्रीटमेंट किया गया है।

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर (एपीसी)

उड़ीसा सरकार

विभागः मिशन शक्ति, उड़ीसा आजीविका मिशन

राज्य के 40 पिछड़े ब्लॉकों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर (एपीसी) का मॉडल स्थापित करना, बाजार की उत्पादन प्रणाली और सेवाओं को प्रभावी तरीके से व्यवस्थित करना तथा लघु और सीमांत किसानों की आय को स्थायी रूप से दोगुना करने के लिए कृषि क्षेत्र में सतत् विकास करना। इस परियोजना के अन्तर्गत 119,785 परिवार लाभान्वित हुए हैं।

जीवि दाः हासाः हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड परियोजना

झारखंड सरकार

विभागः राज्य मनरेगा सेल

झारखंड राज्य के 24 ब्लॉकों के ऊपरी रिज क्षेत्रों में लगभग 3.39 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र को बहाल करना और मिट्टी के कटाव को रोककर जल संरक्षण को बढ़ावा देना। वाटरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण में मनरेगा संरचनाओं को लागू करना और स्थायी आधार पर कम से कम 100,000 लघु और सीमांत परिवारों की आय को दोगुना करना। लगभग 1.50 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल सघनता में सुधार के साथ साथ वाटरशेड क्रियान्वयन के रिज-टू-वैली सिद्धांत पर फ्रंटलाइन पंचायती राज संस्थान, समुदाय और सिविल सोसाइटी संस्थानों के सदस्यों के ज्ञान और कौशल विकास में वृद्धि करना।

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं

बोडोलैंड जनजातियों के जीवन को बदलने पर उच्च प्रभाव वाली परियोजना

बोडोलैंड टेरीटोरियल काउंसिल

"ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स ऑफ बोडोलैंड ट्राइब्स" परियोजना का उद्देश्य चार वर्ष की अवधि में बक्सा और उदलगुरी के दो प्रखण्डों में आदिवासी और आदिवासी समुदायों से संबंधित 40,000 परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलना और उनके सतत् विकास में योगदान करना है। इस परियोजना का उद्देश्य बोडोलैंड के एसटी और आदिवासियों की आजीविका विकास पहल (कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों में वृद्धि के साथ भूमि और जल विकास) के माध्यम से आय के स्तर में वृद्धि करना है।

हाई इम्पैक्ट मेगा वॉटरशेड परियोजना

महाराष्ट्र सरकार

विभाग: राज्य मनरेगा सेल

महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ के 6 जिलों के 28 चयनित ब्लॉकों में गरीब, आदिवासी और अन्य कमजोर परिवारों को मनरेगा के माध्यम से उचित भूमि और जल संरक्षण उपचार उपायों के क्रियान्वयन से लाभ दिलाया जाना है। इस परियोजना से स्थायी आधार पर कम से कम 100,000 लघु और सीमांत परिवारों की आय दोगुनी होने की उम्मीद है।

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में उच्च प्रभाव वाली परियोजनाएं

स्प्रिंग रिजूवेनेशन परियोजना

पश्चिम बंगाल सरकार

विभागः पश्चिम बंगाल ग्रामीण विकास विभाग, राज्य मनरेगा सेल

2017 में, पश्चिम बंगाल ग्रामीण विकास विभाग, मनरेगा सेल और बीआरएलएफ ने संयुक्त रूप से पश्चिम बंगाल के चार उत्तरी जिलों (दार्जिलिंग अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग, और जलपाईगुड़ी) में एक झरनाधारा कायाकल्प कार्यक्रम शुरू किया, इस परियोजना के तहत, 457 झरना के ऊपरी रिज और कैचमेंट क्षेत्रों को उचित उपायों के साथ ट्रीटमेंट किया गया, पानी के निर्वहन में सुधार करते हुए कुल 294 स्प्रिंग्स का सफलतापूर्वक कायाकल्प किया गया।

संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य के साथ तालमेल

- 1 NO POVERTY — गरीबी की समाप्ति
- 2 ZERO HUNGER — भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा
- 5 GENDER EQUALITY — लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त करना
- 6 CLEAN WATER AND SANITATION — सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत् प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- 8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH — सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत् आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार, और बेहतर कार्य को बढ़ावा देना
- 10 REDUCED INEQUALITIES — असमानता में कमी
- 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION — स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना
- 13 CLIMATE ACTION — जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना
- 16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS — सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी, जवाबदेह बनना ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके
- 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS — सतत् विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करने के अतिरिक्ति कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना

राज्य सरकार की साझेदारी के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

70% मनरेगा का निवेश

104 ब्लॉकों में 70% मनरेगा का निवेश प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका संपत्ति बनाने के लिए हुआ है।

1916 करोड़ रुपये के निवेश

1916 करोड़ रुपये के निवेश से 1.89 लाख से अधिक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और आजीविका परिसंपत्तियों का सृजन किया गया।

500,000 से अधिक आदिवासी

500,000 से अधिक आदिवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया।

3,781 उच्च गुणवत्ता GIS आधारित डीपीआर

मनरेगा को वॉटरशेड मोड में निवेश करने के लिए 3781 उच्च गुणवत्ता GIS आधारित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार की गई

बीआरएलएफ ने आर्थिक सहायता के माध्यम से 74 CSOs से अधिक भागीदारों का समर्थन किया और 127.85 करोड़ रुपये का निवेश किया।

मनरेगा सेल और CSOs को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए हाई-टेक GIS प्रयोगशालाओं के साथ 3 राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (SPMUs) की स्थापना की गई

7 राज्य सरकारों, 74 CSO भागीदारों, 3000 से अधिक पंचायती राज संस्थानों और 7 डोनर एजेंसियों के साथ औपचारिक साझेदारी की गई।

3,500 धारा सेवकों, ग्राम रोजगार सहायकों और अग्रिम पंक्ति के पदाधिकारियों को भागीदारी योजना और प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रशिक्षित किया गया।

1.15 लाख से अधिक किसानों को गैर-कीटनाशक प्रबंधन/प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया।

राज्य सरकार की साझेदारी के अन्तर्गत प्रमुख उपलब्धियाँ

880,152

स्थायी कृषि आधारित हस्तक्षेपों के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या

699,106

स्वयं-सहायता समूहों/ उत्पादक समूहों/ उत्पादक कंपनियों या विभिन्न संस्थानों के तहत कवर किए गए परिवारों की संख्या

689,922

भूमि और जल संसाधन विकास के तहत कवर किए गए परिवारों की संख्या

470,372

भूमि और जल संसाधन विकास (हेक्टेयर) के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र

417,588

पशुधन के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या

159,477

गैर-कीटनाशक प्रबंधन / आर्गेनिक फार्मिंग के तहत कवर किए गए परिवारों की संख्या

146,603

अधिकार और एंटाइटलमेंट्स के तहत कवर किए गए परिवारों की संख्या

86,173

वन उत्पादों के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या

83,411

बागवानी के अंतर्गत लाभान्वित परिवारों की संख्या

विशिष्ट परियोजना

विमुक्त/घुमंतू पारधी समाज के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए पायलट परियोजना

बीआरएलएफ ने अपने डीएनटी/एनटी कार्य को संचालित करने के लिए मार्गदर्शन के लिए श्री गिरीश प्रभुने की अध्यक्षता में डीएनटी/एनटी पर एक उपसमिति का गठन किया है। उपसमिति की सिफारिशों पर, बीआरएलएफ ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की दौंड तहसील में 150 पारधी परिवारों की आजीविका की स्थिति में सुधार करना है।

यह परियोजना श्री गिरीश प्रभुने के मार्गदर्शन में कार्यान्वित की जा रही है और काष्ठी रेलवे स्टेशन के पास 10.5 एकड़ भूमि की अप्रयुक्त क्षमता का लाभ उठाने पर केंद्रित है ताकि रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और पारधी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान हो सके। परियोजना के तहत गौशाला का निर्माण किया जा रहा है और गीर वंश की गायों का पालन किया जाएगा। गौ-दूध से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को तैयार किया जाएगा जिसे रेलवे स्टेशन पर बेचा जाएगा। इसके अलावा परियोजना के अन्तर्गत अन्य व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना का नियोजन किया गया है। पारधी समाज के युवा को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए समाज को प्राप्त भूमि में विभिन्न उपक्रम लगाये जाएँगे। वर्तमान में गौशाला के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

बीआरएलएफ का मानना है कि DNT/NT परियोजना का दूसरा चरण पारधी समुदाय के जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। परियोजना का उद्देश्य सतत् आजीविका के अवसर पैदा करके और कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पारधी समुदाय की वित्तीय स्थिरता को बढ़ाना और उन्हें मुख्यधारा की विकास प्रक्रिया में लाना है। बीआरएलएफ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि पारधी समुदाय के पास स्थायी आजीविका के अवसर हों और हम सभी इस समुदाय के जीवन पर इस परियोजना के प्रभाव को देखने के लिए उत्साहित हैं।

क्षमता-वर्धन विभाग के अन्तर्गत कार्यक्रम

क्षमता निर्माण बीआरएलएफ का एक महत्वपूर्ण वर्टिकल है, जो इच्छुक ग्रामीण आदिवासी युवाओं की क्षमताओं के निर्माण की दिशा में कार्यरत है।

सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स (सीपीआरएल)

बीआरएलएफ की स्थापना का एक कारण यह भी था कि, संस्था आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने के लिए कार्य करेगा। "सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन रूरल लाइवलीहुड्स" (सीपीआरएल) बीआरएलएफ और आईआईएचएमआर (IIHMR) विश्वविद्यालय की आदिवासी और ग्रामीण पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण करने की दिशा में किया गया एक पहल है। सीपीआरएल ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए उप-जिला स्तर पर काम कर रहे मौजूदा और महत्वाकांक्षी आदिवासी, ग्रामीण पेशेवरों (18-40 वर्ष) द्वारा ज़मीनी स्तर की चुनौतियों के समाधान का काम करता है, चाहे वह गैर सरकारी संगठनों, सरकारी संस्थानों और पहलों के माध्यम से या पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में हो। सीपीआरएल एक बहु-केंद्र, बहु-विषयक कार्यक्रम है. सीपीआरएल का पहला बैच 15 नवंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था। मार्च 2021 तक, 174 आदिवासी युवाओं के 6 बैच सीपीआरएल का हिस्सा थे। 146 युवाओं ने कोर्स पूरा किया और जमीनी स्तर पर विभिन्न सिविल सोसाइटी संस्थानों और पंचायती राज संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं।

विकास प्रबंधन में एमबीए एवम् ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर – आदिवासी युवाओं के लिए छात्रवृति कार्यक्रम

बीआरएलएफ मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्र के होनहार आदिवासी छात्रों को स्कूल ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, आईआईएचएमआरयू, जयपुर से विकास प्रबंधन में दो वर्षीय एमबीए एवम् शिव नादर विश्वविद्यालय-नोएडा से ग्रामीण प्रबंधन में एमए करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आईआईएचएमआरयू, जयपुर के साथ यह पहल 2017 में एमबीए-ग्रामीण प्रबंधन बैच 2017-19 के लिए छह आदिवासी उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता के विस्तार के साथ शुरू की गई थी। पहले बैच से उत्साहजनक सीख लेते हुए, बीआरएलएफ ने 30 आदिवासी युवाओं का समर्थन किया है, जिनमें से 6 सीपीआरएल के पूर्व छात्र हैं। मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत सिविल सोसाइटी संस्थानों से प्राप्त नामांकनों में से शेष उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की गई है।

पाठ्यक्रम के दो वर्षों में, छात्र कक्षा और क्षेत्र मॉड्यूल के मिश्रण के माध्यम से ग्रामीण प्रबंधन की मूल बातें सीखते हैं। पाठ्यक्रम के पहले वर्ष के दौरान, छात्र अपने पाठ्यक्रम से संबंधित किसी भी विषय पर दो महीने की ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप करते हैं। उन्हें उनकी रुचि के क्षेत्र के आधार पर क्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न ग्रामीण विकास के कार्य करने वाले संगठनों के साथ जोड़ा जाता है। इसी तरह, वे पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में एक शोध प्रबंध का अध्ययन करते हैं।

इसी प्रकार भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन शिव नादर विश्वविद्यालय-नोएडा से ग्रामीण प्रबंधन में एमए करने के लिए पूरी छात्रवृत्ति के माध्यम से 30 योग्य आदिवासी युवाओं का समर्थन कर रहा है। शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस ने सितंबर 2023 से दो वर्षीय एमए इन रूरल मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। यह अपनी तरह का अनूठा बहु-विषयक कार्यक्रम है, जो छात्रों को ग्रामीण भारत की समस्याओं की गहन बहु-विषयक समझ प्रदान करता है एवम् नवीन और दूरगामी समाधान खोजने की उनकी क्षमता का पोषण भी करता है।

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया यूथ फेलोशिप और वीडियो फॉर चेंज

ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया (जीएचसीआई) यूथ फेलोशिप मध्य भारत के आदिवासी युवाओं के लिए एक मंच तैयार करते हुए उन्हें सीखने और उनके आजीविका हेतु एक नया अवसर प्रदान करने की एक पहल है। यह क्षेत्र में सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक संसाधन केंद्र भी है। ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया (जीएचसीआई) यूथ फेलोशिप का विजन फोटोग्राफी के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करने के लिए अभिनव प्रशिक्षण के माध्यम से जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, प्राकृतिक संसाधनों और संधारणीय प्रथाओं के संरक्षण में ग्रामीण और आदिवासी युवाओं को वीडियोग्राफी और कहानी सुनाना इत्यादि के लिए संलग्न, सशक्त और डिजिटल रूप से लैस करना है। ग्रीन हब सेंट्रल इंडिया के पहले चरण में कुल मिलाकर 4 राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, और राजस्थान शामिल हैं, प्रति बैच 25 आदिवासी छात्रों की संख्या के साथ लगातार चार बैचों में 100 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन

बीआरएलएफ में अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन (आर एंड केएम) वर्टिकल ने आदिवासियों के जीवन और आजीविका के मुद्दों पर ज्ञान का भण्डार विकसित किया है। आदिवासी समुदायों के मुद्दों और चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।

वर्टिकल ने मानव विकास के विभिन्न संकेतकों के संदर्भ में आदिवासी समुदायों की वर्तमान स्थिति पर मूल शोध किया है; आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर सरकारी कार्यक्रमों और कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन; राज्य सरकार और सिविल सोसाइटी संस्थानों के साथ स्थापित बीआरएलएफ की भागीदारी के प्रभावों का अध्ययन करता है; और एक ज्ञान केंद्र का विकास करता है जिससे शिक्षाविद, सिविल सोसाइटी संस्थान और सरकार आदिवासियों की समझ विकसित कर सकें।

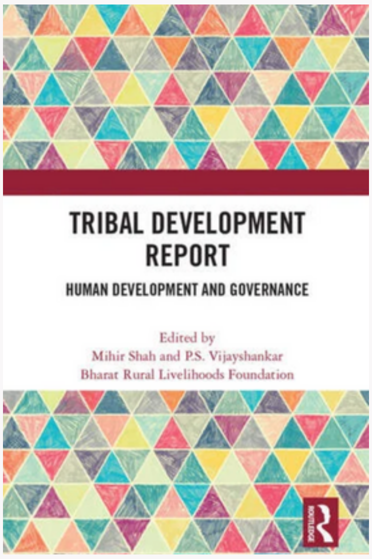

जनजातीय विकास रिपोर्ट

रुटलेज और सीआरसी प्रेस (जुलाई 2022) द्वारा जनजातीय विकास रिपोर्ट दो खंडों में प्रकाशित होने की संभावना है। पहला खंड मध्य भारत में आजीविका, कृषि, प्राकृतिक संसाधनों, अर्थव्यवस्था और प्रवास से संबंधित आदिवासी समुदायों की स्थिति पर केंद्रित है। वे प्रमुख शिक्षाविदों, विषयगत विशेषज्ञों और कार्यकर्ताओं द्वारा लिखे गए थे। दूसरा खंड शासन, मानव विकास, लिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कला और संस्कृति के संदर्भ में आदिवासी समुदायों की स्थिति पर प्रकाश डालेगा। दोनों खंडों का संपादन डॉ. मिहिर शाह और पी.एस. विजय शंकर द्वारा किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय का उत्कृष्टता केंद्र

21 नवंबर 2019 को, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बीआरएलएफ को "जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए विशेष उत्कृष्टता केंद्र (सीओई)" के रूप में मान्यता प्रदान की है। सीओई के रूप में, बीआरएलएफ को मंत्रालय की ग्रांट इन ऐड (जीआईए) योजना की पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाने का काम सौंपा गया था, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों के मूल्यांकन के लिए मानदंड खोजने और यह जांचने के लिए कि क्या गैर सरकारी संगठनों ने परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक क्षमता के लिए एमओटीए से वित्त पोषण के लिए आवेदन किया है। बीआरएलएफ को नए और मौजूदा एनजीओ की स्क्रीनिंग और ग्रेडिंग के लिए उचित परिश्रम करने की जिम्मेदारी भी दी गई थी।

रीमा कच्छप: सफलता की उड़ान

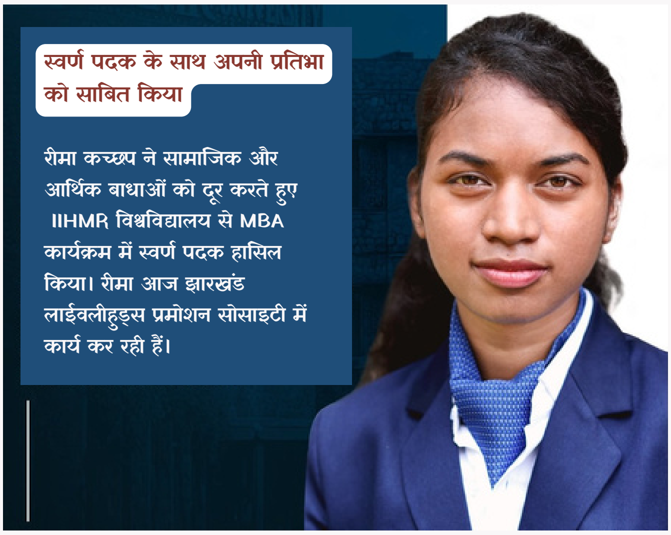

रीमा कच्छप रांची जिले के नामकुन प्रखण्ड में अपने माता-पिता के साथ रहने वाली उरांव समुदाय की हैं। रीमा के माता-पिता किसान हैं; उसका एक बड़ा भाई और तीन बहनें हैं। रीमा ने अपनी स्कूली शिक्षा रांची के जवाहर नवोदय स्कूल से की है और सेंट जेवियर कॉलेज, रांची से रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है।

रीमा को 2018 में बीआरएलएफ द्वारा आईआईएचएमआर यूनिवर्सिटी, जयपुर से एमबीए – रूरल मैनेजमेंट (आरएम) करने के लिए नामांकित किया गया था। एक मेधावी छात्रा रीमा ने अपने पाठ्यक्रम में अच्छा प्रदर्शन किया और पाठ्यक्रम को ग्रामीण परिवेश से संबंधित पाया। सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यावहारिक समझ स्थापित करने के लिए उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा कई क्षेत्र के दौरे और एक्सपोजर प्रदान किए गए थे। उन्होंने 2020 में ग्रामीण प्रबंधन में एमबीए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ता ने उन्हें एमबीए आरएम बैच 2018-20 में स्वर्ण पदक दिलाया।

एमबीए के दौरान, उन्हें कैंपस प्लेसमेंट मिला और उन्होंने झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) में काम करना शुरू कर दिया। प्रखण्ड स्तर की स्थिति से शुरू होकर, वह अब विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) और अति-निर्धन समुदायों के विकास के लिए कार्यरत है। उन्होंने पीवीटीजी कम्युनिटी कैडर के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का भी समन्वय किया। वह उड़ान परियोजना की एंकरिंग करती है, जहां वह प्रगति की निगरानी और देखरेख करती है और कार्यान्वयन टीम को मार्गदर्शन प्रदान करती है।

उन्होंने दो साल के पाठ्यक्रम के माध्यम से सामाजिक चुनौतियों और मुद्दों की गहरी समझ हासिल की। वह एमबीए से मिली शिक्षा का अभ्यास कर रही है। रीमा बीआरएलएफ को अपने भविष्य को आकार देने और उसे स्वतंत्र और साधन संपन्न बनाने में एक विशेष स्थान देती है।

BRLF
भारत रूरल
लाइवलीहुड्स फाउंडेशन

प्रधान कार्यालय: सी-32, दूसरा तल, नीति बाग, नई दिल्ली, 110049
कार्यालय फ़ोन: +91 11 4606 1935 फ़ैक्स: +91 11 4101 338

www.brlf.in